



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 310]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

मामला सं. 08 /2019

**विषय : थाइलैंड से एक्रिलिक फाइबर के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत पाटनरोधी जांच ।**

**सं. 7/18/2019-डीजीटीआर.**—यतः समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां बाद में) अधिनियम कहा गया है और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों की पहचान, मूल्यांकन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए नियमावली (जिसे यहां आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 13/9/1996 को यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 47/एडीडी/1 डब्ल्यू दिनांक 14.10.1997 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी । केन्द्र सरकार ने पाटनरोधी शुल्क लागू किया था । यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के विरुद्ध इस प्रकार लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 26/1/2001- डी जी ए डी दिनांक 7.8.2001 द्वारा शुरू की गई थी और अधिसूचना सं. 26/1/2001-डीजीएडी, दिनांक 6.8.2002 द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे । दिनांक 9.10.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 106/2002-सीमाशुल्क द्वारा यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर केन्द्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 10/7/2006-डीजीएडी दिनांक 8.10.2007 द्वारा शुरू की गई थी और अंतिम जांच परिणाम

दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं. 10.7.2006-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 123/2008-सीमाशुल्क दिनांक 20.11.2008 द्वारा थाइलैंड और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की तीसरी निर्णायक समीक्षा प्राधिकारी द्वारा 15/16/2013-डी जी ए डी दिनांक 24.9.2013 द्वारा शुरू की गई थी और दिनांक 23.3.2015 की अधिसूचना सं. 15/16/2013-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे जिनमें लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 27/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 1.6.2015 द्वारा थाइलैंड और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. यतः, मै. इंडियन एक्रिलिक्स लि., मै. वर्धमान एक्रिलिक लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने थाइलैंड (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की है।
3. यतः तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया पाते हैं कि थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की समीक्षा की आवश्यकता है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. याचिका में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान ही है जिसे अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

*मूल जांच और इसके बाद समीक्षा जांचों में शामिल उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पालिमेर की एक लंबी शृंखला होती है जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है, के भार के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत होता है जिसे आम तौर पर रंग, लंबाई और फाइबर के डेनियर के अनुसार वर्णित किया जाता है। इसका प्रयोग परिधानों, घरेलू मदों के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ किया जाता है और उद्योग में भी इसका काफी प्रयोग होता है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। जहां तक उत्पाद का संबंध है, एक्रिलिक फाइबर का सीमाशुल्क वर्गीकरण 5501.3000, 5503.3000 और 5506.3000 है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।*

5. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहेगा।

#### ख. समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

#### ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए के लिए याचिका इंडियन एक्रिलिक्स लि., मै. वर्धमान एक्रिलिक लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. द्वारा दायर की है। याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

8. प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक याचिकाकर्ता कंपनी ने अग्रिम प्राधिकारी योजना के अधीन और काफी कम मात्रा में पी ओ आई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि न तो वे संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और न ही संबद्ध वस्तु के किसी आयातक के। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है।

**घ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

9. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

**ङ. शामिल देश**

10. वर्तमान जांच में शामिल देश थाइलैंड है।

**च. जांच की अवधि (पीओआई)**

11. जांच अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च 2019 तक की है। क्षति जांच अवधि में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**छ. प्रक्रिया**

12. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा पर आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

**ज. सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**वाणिज्य विभाग**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,**

**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

14. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**झ. समय-सीमा**

15. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की सूचना देने वाले पत्र जारी करने की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।
17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
18. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

22. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2019

**SSR No. 08/2019**

**Subject: - Initiation of Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre from Thailand.**

**F. No. 7/18/2019-DGTR.**—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), initiated the original anti-dumping investigation in respect of the imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP on 13.9.1996 and definitive anti-dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 47/ADD/1W dated 14.10.1997. The Central Government had imposed the anti-dumping duty. The sunset review of the anti-dumping duty so imposed against USA, Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 07.08.2001 and the Final Findings were issued vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 06.08.2002. Definitive anti-dumping duty was levied by the Central Government on the subject goods originating in or exported from USA, Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 106/2002-Customs dated 09.10.2002. Second Sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 10/7/2006-DGAD dated 08.10.2007 and the Final Findings were issued vide Notification No. 10/7/2006-DGAD dated 03.10.2008, recommending continuation of the anti-dumping duty in force. Definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government on the subject goods from Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 123/2008-Customs dated 20.11.2008. Third Sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from Thailand and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 15/16/2013-DGAD dated 24.9.2013 and the Final Findings were issued vide Notification No. 15/16/2013-DGAD dated 23.3.2015, recommending continuation of the anti-dumping duty in force. Definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government on the subject goods from Thailand and Korea RP vide Customs Notification No. 27/2015-Cus (ADD), dated 1.6.2015.

2. Whereas, M/s Indian Acrylics Limited, M/s. Vardhman Acrylics Limited and M/s. Pasupati Acrylon Ltd (hereinafter referred to as 'Petitioners') have filed a review petition for continued imposition of Anti-dumping duty on imports of Acrylic Fibre from Thailand (hereinafter referred to as subject country).

3. Whereas, based on the facts and evidence, the Authority finds prima facie that there is a need to review for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the Thailand.

**A. Product under consideration and Like Articles**

4. The product under consideration in the petition is the same as the original investigations,

which was defined as follows in the final findings

*The product involved in the original investigation and subsequent review investigations is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile, which is a major raw material for production of acrylic fibre. It is broadly described in terms of colour, length and denier of the fibre. It is used for the purpose of manufacturing apparels, household items and it has a great industrial use etc. It is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification of Acrylic Fibre so far as it relates to the product is 5501.3000, 5503.3000 and 5506.3000. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.*

5. The current investigation being a sunset review investigation, the scope of product under consideration remains the same in the previous investigation.

#### **B. Like Article**

6. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules.

#### **C. Domestic Industry & Standing**

7. The petition for initiation of sunset review is filed by Indian Acrylics Limited, M/s. Vardhman Acrylics Limited and M/s Pasupati Acrylon Ltd. The production of petitioner companies is 100% of Indian production of the subject goods in the Country, as there are no other producers of the subject goods in India.

8. On the basis of information furnished, the Authority notes that the one of the petitioner companies have made imports of the subject goods from the subject country during the POI, under advance authorization scheme and that too not in significant quantity. The petitioners have stated that they are neither related to any exporter in the subject country nor to importer of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the petitioner companies as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.

#### **D. Initiation of Sunset Review Investigation**

9. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

#### **E. Country involved**

10. The country involved in the present investigation is Thailand.

**F. Period of Investigation (POI)**

11. The period of investigation is April 2018- March 2019. The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and the period of investigation.

**G. Procedure**

12. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

**H. Submission of Information**

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Trade Remedies**  
**Department of Commerce**  
**Ministry of Commerce and Industry**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building**  
**5, Parliament Street, New Delhi – 110001**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

**I. Time Limit**

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise of the anti-dumping measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

**J. Submission of Information on Confidential Basis**

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-

confidential information. Two (02) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **K. Inspection of Public File**

22. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

#### **L. Non-Cooperation**

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority